ग्वालियर | बुधवार | 7 जनवरी 2026 | वर्ष 31 | अंक 143 | पृष्ठ 20 | मूल्य रु. 6.00 navabharat.com twitter.com/Nava_Bharat fb.me/NavaBharat.Social

नव भारत

राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

5 2.89 करोड़ वोटरों के नाम कटे

6 ट्रंप ने दिखाया गजब का खेल हड़पेगा वेनेजुएला का तेल

7 घरेलू मांग बनेगी अर्थव्यवस्था की ताकत

10 सबालेंका की जीत से शुरुआत

एक नजर में

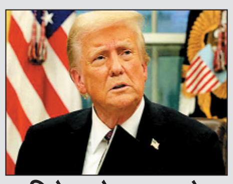

विरोध को कम करने ट्रंप का नया पैंतरा

वॉशिंगटन. इन दिनों दुनिया में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चर्चा का विषय बने हुए हैं. उनके हाल के कार्रवाई (वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के अपहरण) ने तो दुनिया को चौंका दिया. उनकी इस कार्रवाई का अमेरिका में ही लगातार विरोध हो रहा है. विरोध को करने राष्ट्रपति ट्रंप ने नया पैंतरा चला है. उन्होंने किया है कि उनके द्वारा लगाए गए टैरिफ से अमेरिका को 600 अरब डॉलर मिलने वाला है. इसकी जानकारी उन्होंने ट्रूथ सोशल के जरिए दी. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दावा किया कि अमेरिका को टैरिफ से 600 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक धन प्राप्त होंगे.

हाइड्रोजन कार स्वच्छ गतिशीलता का भविष्य

नई दिल्ली. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी को हाइड्रोजन कार अपनाने पर मंगलवार को बधाई दी. उन्होंने कहा कि यह कार स्वच्छ गतिशीलता का भविष्य है. नितिन गडकरी ने एक्स पोस्ट में कहा कि उन्होंने जोशी के साथ इस उल्लेखनीय वाहन में थोड़ी ड्राइव का आनंद लिया, जो स्वच्छ गतिशीलता के भविष्य को दर्शाता है. गडकरी ने कहा, हाइड्रोजन भारत की ऊर्जा संक्रमण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

आंध्र प्रदेश में गैस के कुएं में लगी भीषण आग

मोरी. डॉ. बीआर आंबेडकर कोनासीमा जिले में गैस के एक कुएं में आग लग गई. खबर लिखे जाने तक आग पर काबू नहीं पाया गया था. आग बुझाने के लिए मुंबई और दिल्ली से तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) की विशेषज्ञ टीम पहुंची. एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि आग की तीव्रता में कमी नहीं आई है. ओएनजीसी के स्वामित्व वाले मोरी-पांच कुएं में गैस रिसाव के बाद सोमवार को मोरी और इरसुमंदा गांवों के पास करीब 25 मीटर के भूभाग में आग भड़क उठी थी और 20 मीटर ऊंची लपटें देखी गईं.

इंसानों से ज्यादा कुत्तों पर आ रहीं याचिकाएं

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों में दाखिल हो रही याचिकाओं की बाढ़ पर हैरानी जताई है. मंगलवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप मेहता ने टिप्पणी की कि इंसानों से संबंधित मामलों में भी आमतौर पर इतनी बड़ी संख्या में अंतरिम आवेदन नहीं आते, जितने कुत्तों के मुद्दे पर आ रहे हैं. कोर्ट ने आश्वासन दिया कि बुधवार को सभी पक्षकारों की दलीलें सुनी जाएंगी. जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह टिप्पणी तब की जब दो वकीलों ने उनके सामने आवारा कुत्तों से संबंधित मामला उठाया. एक वकील ने बताया कि उन्होंने इस मामले में अंतरिम आवेदन दाखिल किया है.

गुस्ताखी माफ

मैं आज भी निर्दोष राष्ट्रपति : मादुरो

यूएस कोर्ट में नार्को-टेररिज्म के आरोपों से वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो का इंकार

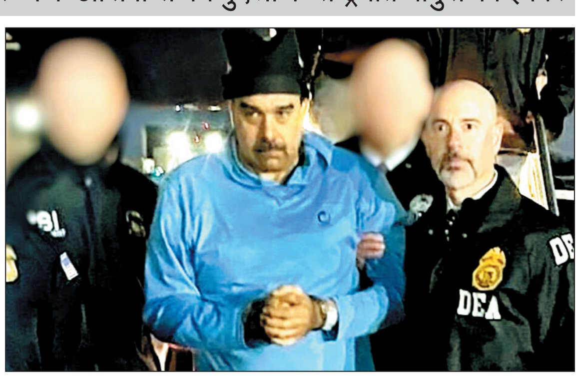

वॉशिंगटन, 06 जनवरी. वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका लाकर न्यूयॉर्क के मैनहैटन स्थित फेडरल कोर्ट में पेश किए जाने से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई है. हथकड़ियों में अदालत पहुंचे मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस पर ड्रग तस्करी और अवैध हथियारों से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं. वहीं वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अदालत में खुद को निर्दोष बताया. उन्होंने कहा, मैं बेगुनाह हूं, मैं आज भी अपने देश का राष्ट्रपति ह

अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही जांच का नतीजा है. वहीं मादुरो ने खुद को निर्दोष बताते हुए अब भी वेनेजुएला का राष्ट्रपति होने का दावा किया है. इस मामले ने अमेरिका-वेनेजुएला संबंधों को और तनावपूर्ण बना दिया है और वैश्विक स्तर पर भी तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं.

वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति मादुरो के वकील ने उनकी गिरफ्तारी को मिलिट्री एबडक्शन यानी सैन्य अपहरण करार दिया और कहा कि इस मामले में लंबी और जटिल कानूनी लड़ाई होगी. फिलहाल मादुरो ने रिहाई की मांग नहीं की है, वहीं मादुरो की पत्नी सिलिया फ्लोरेस के वकील ने गंभीर चोटों का हवाला देते हुए मेडिकल जांच की मांग की.

ट्रंप के विरोध में आए सात यूरोपीय देश, पत्र पर किए साइन

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर दिए गए बयान पर डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने सोमवार को करारा हमला बोला और उन्होंने कहा कि डेनमार्क को अमेरिका वेनेजुएला समझने की कोशिश न करे. फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन और डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को लेकर एक संयुक्त बयान जारी किया है. इसमें कहा गया है कि आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा यूरोप की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है और ग्रीनलैंड के भविष्य पर फैसला लेने का अधिकार सिर्फ डेनमार्क को है.

मादुरो की पत्नी की आंखों में जख्म, पसलियों में फ्रैक्चर

रिपोर्ट में खुलासा

- अमेरिकी ऑपरेशन के दौरान हुई जख्मी

अमेरिकी सेना के वेनेजुएला ऑपरेशन में अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की पत्नी सिलिया फ्लोरेस को काफी चोटें आई हैं. रिपोर्ट के मुताबिक 69 साल की फ्लोरेस जब न्यूयॉर्क कोर्ट में पेश हुईं तब उनके चेहरे पर दो पट्टियां लगी थीं. एक पट्टी आंख के ऊपर और दूसरी माथे पर थी. उनकी दाहिनी आंख पर चोट का नीला निशान साफ दिखाई दे रहा थी. फ्लोरेस के वकील मार्क डोनेली ने कोर्ट को बताया कि ये चोटें उस वक्त लगीं, जब अमेरिकी सेना ने उन्हें पकड़ा था.

कोर्ट में पेशी के दौरान थके नजर आए पति-पत्नी

सुनवाई के दौरान फ्लोरेस को डिफेंस टेबल पर बैठने के लिए सहारे की जरूरत पड़ी. वहीं मादुरो खड़े होकर स्पेनिश भाषा में बोले, जिसका अनुवाद कोर्ट के नियुक्त अनुवादक ने किया. बताया गया कि दोनों शारीरिक रूप से काफी थके और कमजोर नजर आ रहे थे.

बता दें 63 साल के मादुरो और 69 साल की फ्लोरेस को अमेरीका ने 3 जनवरी, शनिवार को वेनेजुएला में अमेरिकी सेना ने हिरासत में लिया था.

क्षेत्रीय अस्थिरता की संभावना को लेकर चिंतित : गुटरेस

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिकी कार्रवाई और राष्ट्रपति मादुरो को पकड़े जाने के बाद वेनेजुएला में बढ़ती अस्थिरता पर चिंता जताई है, यद्यपि अमेरिका ने आश्वासन दिया है कि इस मध्य अमेरिकी देश पर कब्जा करने की उसकी कोई योजना नहीं है. वह 'चिंतित हैं कि तीन जनवरी की सैन्य कार्रवाई के संबंध में अंतरराष्ट्रीय कानून के नियमों का सम्मान नहीं किया गया है.

अब मप्र में ई-गवर्नेंस, मंत्रियों को कैबिनेट में मिला टैबलेट

- अब कैबिनेट का एजेंडा टैबलेट पर ही मिलेगा

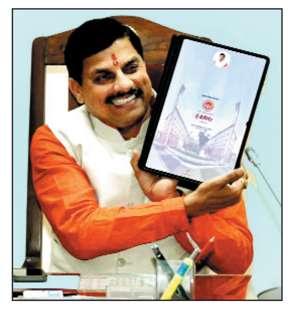

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 6 जनवरी. मप्र सरकार ने ई-गवर्नेंस की ओर मंगलवार को बड़ा कदम बढ़ा दिया है. मंत्रालय में मंगलवार को कैबिनेट शुरू होते ही सबसे पहले मंत्रियों को टैबलेट का वितरण किया गया, अब कैबिनेट से जुड़ी सभी जानकारी टैबलेट पर ही मिलेगी. यहां तक कि अब तक लिये निर्णयों की जानकारी भी टैबलेट पर एक क्लिक में मिल जाएगी. मंत्रियों के साथ ही भारसाधक सचिवों को भी टैबलेट दिये गये.

कैबिनेट के सदस्यों ने टैबलेट मिलने पर खुशी जताई और बाकायदा मुख्यमंत्री का मेजे थपथपाकर इस नई पहल का स्वागत करते हुए आभार भी जताया. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कैबिनेट सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि मप्र में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसके तहत ई-कैबिनेट की पहल हुई है. ई-कैबिनेट एप्लीकेशन के संबंध में संबंधितों को जरुरी प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है. यह एप्लीकेशन आधुनिक तकनीक, पेपरलैस, सुरक्षित और ऐसी गोपनीय प्रणाली है, जिसे कैबिनेट सदस्य कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार अवलोकन कर सकते हैं. मुख्य रूप से कैबिनेट की कार्य सूची देखने, ई-कैबिनेट एप्लीकेशन द्वारा पूर्व की बैठकों में लिए गए निर्णयों का पालन-प्रतिवेदन देखने में सुविधा होगी. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि पारदर्शिता और समय की बचत के लिए मंत्रि-परिषद सदस्य नई व्यवस्था का पूरा लाभ लेंगे. शुरू में कैबिनेट बैठक का एजेण्डा भौतिक एवं डिजिटल रूप दोनों फार्मेट में भेजा जाएगा.

बांग्लादेश में दुकान संचालक की हत्या

24 घंटे में दूसरी हत्या

18 दिनों में छह हिंदुओं की हत्या

ढाक , 6 जनवरी. बांग्लादेश के नरसिंदी जिले में सोमवार रात एक हिंदू दुकानदार की धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान 40 वर्षीय शरत चक्रवर्ती मणि के रूप में हुई है. यह बीते 18 दिनों में छठे हिंदू व्यक्ति की हत्या है.

शरत चक्रवर्ती मणि पलाश उपजिला के चारसिंदूर बाजार में अपनी किराना दुकान चला रहे थे. इसी दौरान अचानक पहुंचे अज्ञात हमलावरों ने उन पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए. गंभीर रूप से घायल मणि को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है. बता दें कि 19 दिसंबर को मणि ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर देश में बढ़ती हिंसा पर चिंता जताई थी और अपने इलाके को मौत की घाटी बताया था.

बता दें कि सोमवार को जेसोर जिले के मोनिरामपुर इलाके में एक आइस फैक्ट्री मालिक राणा प्रताप बैरागी की सार्वजनिक रूप से हत्या हुई थी. वहीं एक हिंदू विधवा महिला से गैंगरेप किया था. आरोपियों ने रेप के बाद उसे पेड़ से बांधकर पीटा भी था.

क्लैट प्रश्नपत्र लीक मामले की जांच के निर्देश के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय में कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (क्लैट) 2026 के परीक्षा से पहले कथित प्रश्न-पत्र लीक की समयबद्ध जांच कराने की मांग की एक याचिका दायर की गई है. देशके प्रमुख विधि कॉलेजों में प्रवेश के लिए सात दिसंबर को आयोजित क्लैट 2026 परीक्षा आयोजित होने से पहले प्रश्न पत्र लीक के आरोपों के बाद यह जांच के दायरे में आ गई है. कई अभ्यर्थियों ने इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए अदालत का रुख किया है. यह भी अनुरोध किया है कि आरोप सही पाए जाते हैं तो पुनर्परीक्षा का आदेश दिया जाए.

शाह को हत्यारा कहने पर राहुल गांधी तलब

सुलतानपुर, 06 जनवरी. गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मंगलवार को सुल्तानपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई. करीब 40 मिनट चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया है. उन्हें 19 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा है.

राहुल गांधी के वकील ने गवाह राम चंद्र दुबे से जिरह पूरी की. शिकायतकर्ता ने कहा- अब हमारी तरफ से कोई गवाह पेश नहीं किया जाएगा. जस्टिस शुभम वर्मा ने धारा 313 के तहत राहुल गांधी को तलब किया है. उन्हें खुद कोर्ट में आना होगा. इसका मतलब है कि अदालत राहुल को अपने खिलाफ आए सबूतों पर सफाई देना चाहती है, जिससे बिना सुने किसी को दोषी न ठहराया जाए.

राहुल के खिलाफ यह मामला 7 साल पहले कर्नाटक में अमित शाह के खिलाफ की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है. राहुल ने 2018 में कर्नाटक चुनाव के दौरान कहा था कि जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है, उसका अध्यक्ष हत्या का आरोपी है. इसके बाद सुल्तानपुर के भाजपा नेता विजय मिश्र ने 4 अगस्त, 2018 को राहुल के खिलाफ मानहानि का केस दायर किया था.

रन-थ्रू ट्रेनों का ऐलान अनिवार्य

- मुरादाबाद रेल मंडल के नए डीआरएम ने दिए आदेश
- लोको पायलटों के परिजनों से अपील

मुरादाबाद, 06 जनवरी. खुर्जा जंक्शन और रोजा में हुई रेल घटनाओं के बाद रेलवे प्रशासन सतर्क हो गया है. मुरादाबाद रेल मंडल के नए डीआरएम राजकुमार सिंह ने यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेनों के सुरक्षित संचालन को लेकर कड़े कदम उठाए हैं.

इसी कड़ी में अब छोटे स्टेशनों पर भी रन-थ्रू ट्रेनों का अनाउंसमेंट अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे पटरियों के पास मौजूद यात्री सतर्क रह सकें. 29 दिसंबर को खुर्जा जंक्शन पर एक पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी आमने-सामने आ गई थीं. हालांकि, लोको पायलट की सूझबूझ से ट्रेन 200 मीटर पहले रुक गई और बड़ा हादसा टल गया. वहीं, 24 दिसंबर को रोजा में गरीब रथ की चपेट में आने से पांच लोगों की जान चली गई थी. डीआरएम ने लोको पायलटों के साथ बैठक कर उनकी काउंसिलिंग की. उन्होंने निर्देश दिए कि किसी भी शंका की स्थिति में वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत सूचित करें. इस दौरान एक अनूठी अपील लोको पायलटों के परिजनों से भी की गई. उनसे आग्रह किया गया कि वे सुनिश्चित करें कि लोको पायलट ड्यूटी पर जाने से पहले घर पर पूरी नींद लें.

कार्तिगई दीपम जलाने का फैसला बरकरार

कोई राज्य इतना नीचे न गिरे : हाईकोर्ट

चेन्नई, 06 जनवरी. मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ की डिवीजन बेंच ने मंगलवार को सिंगल बेंच के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें तिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर स्थित प्राचीन पत्थर के दीप स्तंभ (दीपथून) पर अरुल्मिगु सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर के प्रतिनिधियों द्वारा कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी गई थी.

यह स्थान हजरत सुल्तान सिकंदर बादशाह औलिया दरगाह के निकट है. सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ राज्य प्राधिकारी, दरगाह प्रबंधन और तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने याचिका दायर की थी.

हालांकि डिवीजन बेंच ने इन लोगों द्वारा कोई ठोस सबूत पेश करने में असफल बताया, जो यह साबित कर सके कि आगम शास्त्र के अनुसार दीप जलाना प्रतिबंधित है.

न्यायमूर्ति जी. जयचंद्रन और न्यायमूर्ति केके रामकृष्णन की खंडपीठ ने कहा कि यह मामला रेस ज्यूडिकाटा से प्रभावित नहीं है, क्योंकि पूर्व के किसी भी मुकदमे में इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय नहीं दिया गया था. खंडपीठ ने तीखी टिप्पणी करते हुए राज्य प्रशासन की दलीलों पर सवाल उठाए. पीठ ने अपने आदेश में कहा- यह हास्यास्पद और अविश्वसनीय है कि शक्तिशाली राज्य को यह डर है कि वर्ष में एक विशेष दिन मंदिर के प्रतिनिधियों द्वारा पत्थर के स्तंभ पर दीप जलाने से सार्वजनिक शांति भंग हो जाएगी. ऐसा तभी हो सकता है अगर राज्य खुद ऐसी अशांति को प्रायोजित करे. हम प्रार्थना करते हैं कि कोई राज्य अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए इतना नीचे न गिरे.

भारत में एआई जन-जन तक पहुंचेगा : वैष्णव

- एआई को समावेशी और सुलभ बनाने पर केन्द्र का जोर

जयपुर, 6 जनवरी. केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि एआई आने वाले समय में मानव जीवन का अभिन्न अंग बनेगा और हर व्यक्ति, हर घर तथा हर उद्यम तक इसकी पहुंच होगी तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में एआई को समावेशी, सुलभ और जनोपयोगी बनाने की दिशा में ठोस एवं दूरदर्शी कदम उठाए जा रहे हैं.

श्री वैष्णव ने आज यहां जेईसीसी में आयोजित राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 के उद्घाटन सत्र कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर यह बात कही.

उन्होंने कहा कि कम समय में भारत ने एआई मशीनों और तकनीक के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है और आज देश की एआई क्षमताएं विश्व स्तर पर चर्चित है. एआई कंप्यूट सुविधा को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से कॉमन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है, जिसके अंतर्गत देशभर में कम लागत पर उन्नत कंप्यूट संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं.

भारत आज विश्व के शीर्ष तीन देशों में शामिल

उन्होंने कहा कि एआई विकास के क्षेत्र में भारत आज विश्व के शीर्ष तीन देशों में शामिल है. चीन, अमेरिका और भारत एआई डेवलपमेंट में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं. भारत की आईटी इंडस्ट्री देश की अर्थव्यवस्था की बड़ी ताकत है और एआई के माध्यम से यह शक्ति और सुदृढ़ होगी. मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और नवाचार आधारित इकोसिस्टम भारत को वैश्विक स्तर पर एआई क्षेत्र में नेतृत्व की ओर ले जा रहे हैं. एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल टेक्नोलॉजी भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने में निर्णायक भूमिका निभाएंगी. उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से राजस्थान तकनीकी नवाचार का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा और देश के युवाओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा.

सख्ती कोर्ट ने कहा- इस घटना ने देश के सबसे स्वच्छ शहर की छवि को नुकसान पहुंचाया

दूषित पानी मामले में हाई कोर्ट सख्त, मुख्य सचिव तलब

429 नए मरीज सामने आए

नव भारत न्यूज

इंदौर, 6 जनवरी. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में मंगलवार को दूषित पेयजल से जुड़े पांच मामलों की एक साथ सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि इस घटना ने देश के सबसे स्वच्छ शहर की पहचान रखने वाले इंदौर की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया है.

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल इंदौर ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है और इससे किसी भी हाल में समझौता नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने संकेत दिए कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी तय की जा सकती है. साथ ही यह भी कहा गया कि यदि पीड़ितों को दिया गया मुआवजा अपर्याप्त पाया गया तो उस पर भी उचित निर्देश जारी किए जाएंगे. इस संबंध में दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव को 15 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं.

महेश गर्ग एवं अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बगड़िया, उनके साथ सुश्री सैली पुरंदरे, मनीष यादव और रितेश इनानी उपस्थित रहे, जबकि राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राहुल सेठी के साथ शासकीय अधिवक्ता आदित्य गर्ग तथा नगर निगम इंदौर की ओर से अधिवक्ता ऋषि तिवारी ने पक्ष रखा.

पीड़ितों को दिए दो दो लाख के चेक...

जिला प्रशासन ने दूषित पानी से हुई मौतों के मामलों में मृतकों के परिजनों को राहत देते हुए दो दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए. जिन परिजनों को चेक दिए गए, उनमें उर्मिला पति अलगू राम, मंजुला पति दिगंबर बाघे, सीमा पति गौरीशंकर, अव्यान पिता सुनील साहू, ताराराानी कोरी, नंदलाल सिद्धार्थ पाल, उमा बिहारीलाल कोरी, संतोष पिता कल्याण, सुमित्रादेवी पति रामेश्वर दास, गोमती पति गोपाल, अशोक पिता मोतीलाल, रामकली पति जगदीश, शंकरलाल जीवनलाल बरेडे, श्रवण पिता नाथू और गीताबाई ध्रुवकर शामिल हैं.

मंगलवार को 429 नए मरीज सामने आए. फिलहाल 99 अस्पतालों में भर्ती हैं, जिनमें 16 की हालत गंभीर है और उन्हें आईसीयू में रखा है. मरीजों के लिए एमवाय अस्पताल, अरविंदो अस्पताल और बच्चों के लिए चाचा नेहरू अस्पताल में विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं, जबकि निजी अस्पतालों में इलाज कराने वालों को भी नि:शुल्क जांच और दवाइयों के निर्देश दिए हैं.